

उस के साथ ही आप फौरन कोलेबरेशन भी कर रहे हैं, यदि हां, तो उस में कितने फौरन एक्सचेंज की जरूरत होगी और आज जो स्कूटर्स ब्लॉक में बिक रहे हैं और काफी लोगों को उनके मिलने में दिक्कत हो रही है तो क्या मंत्री महोदय यह विश्वास दिला सकते हैं कि चौथी पंच-वर्षीय योजना के बाद जितनी आवश्यकता है उतने स्कूटर्स हिन्दुस्तान के लोगों को मिल पायेंगे ? देश में कितने स्कूटरों की आवश्यकता है और कितना अभी उन का पोडकेशन है ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह फैक्टरी बन कर तैयार हो जायगी तो एक लाख स्कूटर्स इस फैक्टरी में बनेंगे। इस के अलावा इस वक्त जो कंपैसिटी है वह करीब 50,000 स्कूटरों के आसपास की है। दो, तीन फैक्टरीज उन को बना रही है और इस हिसाब से जब यह साथ हो जायेंगे तो करीब डेढ़ लाख स्कूटर्स यहां सालाना बनने लगेंगे और हमें आशा है कि इससे जो ज्यादातर मांग इस देश की है वह पूरी हो जायगी। अब-उस के बीच में अगर कोई बहुत ज्यादा मांग स्कूटर्स की बढ़ती है तो उस समय हम उसे देख सकते हैं लेकिन हमारा भंदाज है कि इस से मांग पूरी हो जायगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : जो इस के लिए मंत्री महोदय फौरन कोलेबरेशन करेंगे उस में फौरन एक्सचेंज कितना लगेगा उस का जबाब नहीं दिया है।

श्री दिनेश सिंह : स्टेटमेंट में दिया है। उसे पढ़ लीजियेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा है कि जो सबाल किया जाय उस का जबाब मंत्री महोदय को देना चाहिए तो मैंने जो फौरन कोलेबरेशन के बारे में पूछा है कि उस में कितना फौरन एक्सचेंज लगेगा उस

के बारे में उनका जबाब नदारद है।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं अभी एक वक्तव्य देने वाला हूँ। माननीय सदस्य मेहरबानी करके उस ससय तक इंतजार करें तो उन को यह मालूम हो जायेगा।

18 अगस्त, 1970 को उत्तर बिधे जाने के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उद्योग

\*459. श्री राम गोपाल शालब ले :  
श्री जगन्नाथ राव जोशी :  
श्री ओंकार लाल बेरवा :  
श्री शारदा नन्ब :  
श्री हुकम चन्द कछबाय :

क्या औद्योगिक बिकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग अलग उद्योगों की संख्या कितनी है जिनमें एक करोड़ रुपये और इससे अधिक पूंजी लगी हुई है ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में उक्त उद्योगों के स्वामी। उद्योगपतियों के क्या नाम है ; और

(ग) इन गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 1967 में कितनी पूंजी लगी हुई थी ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) to (c). At the beginning of the current financial year, there were 85 undertakings in the Public Sector under the management and control of the Central Government with capital investment of rupees one crore or more. Besides these, there are 12 undertakings in which the Government have invested funds without having direct responsibility for the day-to-day management. The details are

available in the annual report on the working of Industrial and Commercial undertakings of the Central Government for 1968-69 published by the Bureau of Public Enterprises. There are also several undertakings in the public sector looked after by the various State Governments either with or without Central Government participation in their management and control.

Government does not maintain a day-to-day record of the number of enterprises in the private sector under different levels of investment, nor the names of entrepreneurs or other details of capital invested in each of these enterprises on a year-to-year basis. However, in connection with the monopolies Inquiry Commission Report, a list had been compiled in respect of 75 Business Houses listed in the Report and as per this list, there were at that time 839 industrial units belonging to these Business Houses having an investment of Rs. 1 crore and more. It is estimated that by now the number of industrial units owned by these 75 Business Houses would be in the vicinity of 900.

श्री राम गोपाल शालवाले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में 75 व्यापार गृहों की सूची तैयार की गई थी जोकि एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में दी गई हैं। उस सूची के अनुसार इन व्यापार गृहों के जहां पहले एक करोड़ या उस से अधिक के विनियोजन वाले उस समय 839 औद्योगिक कारखाने थे जबकि अब ऐसा अनुमान है कि इन 75 व्यापार गृहों के औद्योगिक कारखानों की संख्या लगभग 900 तक हो गई होगी।

मैं जानना चाहता हूँ कि आप ने इन 75 लोगों को ही लाइसेंस दिये हैं जिनके कि पहले 839 कारखाने थे और जिनकी कि संख्या अब 900 हो गई है तो उन में क्या कोई नये क्षेत्र भी हैं जिनको कि आपने नये लाइसेंस दिये हैं और नये कारखाने लगाने की इजाजत थी है या जहाँ पुराने लोगों में सारे देश की सम्पत्ति बांटना चाहते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा प्रांतीय व्यापार मंत्री (श्री विनेश सिंह) : जी नहीं। माननीय सदस्य जानते हैं कि पूरी कोशिश यह हो रही है कि ज्यादा रे ख़यादा जो इस का बेस है वह बढ़े और जो लोग ज्यादा बढ़ गये हैं उन को सिर्फ़ खास खास बजह से खास खास काम के लिए ही लाइसेंस दिया जाय। हमारी यह कोशिश है कि जो छोटे उद्योग वाले हैं उन की हम ज्यादा मदद करें।

श्री राम गोपाल शालवाले : यह जो पहले 839 थे और अब 900 हो गये तो उन में से कितनों को दिये गये इस का जबाब दीजिये ?

श्री विनेश सिंह : वह जो हमारा पब्लिकेशन होता है उस में सब दिया रहता है कि किस किस को लाइसेंस मिला है। उस हमारे पब्लिकेशन में जितने लाइसेंस मिलते हैं वह सब छपे रहते हैं और उस की कोपी लाइब्रेरी में रक्खी हुई है।

श्री राम गोपाल शालवाले : मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में जितने सरकारी कारखाने आप ने अब तक स्थापित किये वह सब घाटे में चल रहे हैं, एक भी सरकारी कारखाना नफे में नहीं चल रहा है, अगर कोई एक भी ऐसा हो तो मंत्री महोदय क्या उस का नाम बतला सकते हैं ? इस के बिपरीत गैर सरकारी क्षेत्र में चलने वाले कारखाने मुनाफ़ा कमाते हैं लेकिन अगर मंत्री महोदय का विचार हो कि वह घाटे में चल रहे हैं तो उस का वह नाम बतलायें ?

श्री जगजि भूषण : जो विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान में अपनी मोनोपली रखती हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ एक सिग्रेट कम्पनी का, खास तौर से सिग्रेट बनाने वाली बज़ीर मुलतान कम्पनी जिसने कि अपने औद्योगिक एक्सपेंस के लिए सरकार से प्रार्थना की है। अब